राष्ट्रपति शासन से महाराष्ट्र में गन्ना पेराई शुरू होने पर दुविधा

[जयश्री भोसले। पुणे]

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने से 2019-20 के गन्ना पेराई सीजन की शुरुआत को लेकर अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली कमेटी पेराई शुरू करने की तारीख तय करती रही है, जिसके बाद राज्य की मिलें काम शुरू करती हैं। राज्य सरकार की ओर से तारीख तय होने के बाद शुगर कमिश्नर का ऑफिस जांच करता है कि मिलों ने अपने सभी कानूनी दायित्वों को पूरा कर लिया है या नहीं और गन्ना किसानों का बकाया चुका दिया है या नहीं। इसके बाद वह मिलों को लाइसेंस जारी करते हैं। सरकार की ओर से तय तारीख से पहले काम शुरू करने वाली मिलों को जुर्माना देना पड़ता है।

राज्य की मिलें मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली कमेटी की ओर से पेराई शुरू करने की तारीख तय करने के बाद काम शुरू करती रही हैं

शुगर कमिश्नर ऑफिस के अधिकारियों ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया कि उन्होंने राज्य के प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर पेराई सीजन 25 नवंबर से शुरू करने का सुझाव दिया है।

महाराष्ट्र में मॉनसून के बाद अक्टूबर और फिर नवंबर के पहले हफ्ते में हुई भारी बारिश से राज्य की को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रियों ने सरकार से पेराई सीजन 1 दिसंबर से शुरू करने का आग्रह किया था।

कोल्हापुर में शुगर इंडस्ट्री से जुड़े पी जी मेढ़े ने बताया, 'हालांकि अब हम चाहते हैं कि पेराई सीजन 20 नवंबर से शुरू हो। बारिश बंद होने के बाद कर्नाटक की मिलों ने पेराई शुरू कर दी है। उन्होंने कोल्हापुर से गन्ना लेना शुरू कर दिया है।' वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बी बी थॉम्बरे ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में पेराई शुरू करने में देरी करना इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक साबित होगा।

उन्होंने कहा, 'हम कटाई मजदूरों को एडवांस में भुगतान कर चुके हैं। ये मजदूर अब उन राज्यों में जा रहे हैं जहां मिलों में काम शुरू हो गया है। मराठवाड़ा की कुछ मिलें पेराई सीजन की तारीख के बारे में सरकारी फैसले का इंतजार किए बगैर 15 नवंबर से काम शुरू कर सकती हैं।' इस साल राज्य में गन्ने का रकबा घटकर लगभग 8 लाख हेक्टेयर रहा जो 2018-19 में लगभग 1,16,500 हेक्टेयर था। इसके अलावा कर्नाटक की सीमा से लगे जिलों के मिलर्स गन्ने की अवैध बिक्री से चिंतित भी हैं।

Economic Times

15/11/19